**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 122 वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त**

(फाईल सं. 1/13/2019–समन्वय)

दिनांक : 11.12.2019 समय : 03.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003.

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. डॉ नंदकुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य
4. श्री ए.के.सिंह, सचिव
5. के. तऊथांग, संयुक्त सचिव
6. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
7. श्री एस.पी.मीना, सहायक निदेशक
8. श्री राकेश कुमार दुबे, सहायक निदेशक (प्रशासन)
9. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
10. श्री वाई.के.बंसल, अनुसंधान अधिकारी
11. श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
12. श्री हरिराम मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक
13. श्री के. पी. सिंह, सलाहकार

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मंदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिया गए:

सत्यमेव जयते

**No.1/13/2019-Coord.**
**Government of India**
**National Commission for Scheduled Tribes**
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 13th December, 2019

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
3. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
4. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

**Subject: Summary Record of discussions of 122th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 11.12.2019 at 3:00 P.M.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 122th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 11.12.2019 at 3:00 P.M. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P Meena)
Assistant Director

Copy for necessary action, a copy of the Summary Record of discussions of 122th meeting of NCST is enclosed. The action taken report in the matter may be intimated to Coord. Section by 10.01.2020.

(i) Director
(ii) Deputy Secretary
(iii) Assistant Director (Coord&RU-II)
(iv) Assistant Director (Admin&RU-III)
(v) Assistant Director (RU-I & OL)
(vi) Research Officer (RU-IV)

Copy for information of the Summary Record of discussion of 122th Meeting of NCST:

1. PS to Hon'ble Chairman, NCST
2. PA to Hon'ble Member(HKD), NCST
3. PS to Hon'ble Member(HCV), NCST
4. PS to Hon'ble Member(MCI), NCST
5. Sr.PPS to Secretary, NCST
6. PA to Joint Secretary, NCST
7. Secretary, MoTA, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.1 | त्रिपुरा राज्य के संबंध में भारत के संविधान में अधिसूचित अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन हेतु ड्राफ्ट कैबिनेट नोट। |

**फाइल सं0 Cabinet Note/02/MTA/2019/RU-II**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त विषय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार के दिनांक 10.09.2018 के पत्र संख्या SSJETA/WCD-08/2017/534/183 की प्रति को संलग्न करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय से दिनांक अक्टूबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15025/02/2013–सी एंड एलएम–1 की एक प्रति भेजी गई जिसे आयोग ने जुलाई–अगस्त, 2019 तथा सितम्बर, 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त किया गया।

2. उपरोक्त वर्णित विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं0 12016/15/2001-TA/C&LM-1(130) दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 की प्रति अग्रेषित किया जो आयोग को ड्राफ्ट कैबिनेट नोट के साथ अक्टूबर, 2019 को प्राप्त हुआ।

3. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता हे कि भारत के संविधान द्वारा इस राज्य को जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष जिम्मेदारी का आदेश देता है। संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड(25) में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा इस प्रकार की दी गई है कि "अनुसूचित जनजाति अर्थात् ऐसी जनजातियां या जनजातीय समूह या भागों या दाय जिसके तहत ऐसी जनजातियां या जनजातीय समूह को संविधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति समझा जायेगा।" उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति का प्रथम विनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश के अधिसूचना द्वारा होता है। इसके उपरांत अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ भी शामिल करने या निकालने के लिए तथा अन्य संशोधनों के लिए केवल संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।

4. अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ भी शामिल करने या निकालने के लिए खंड (1) के तहत एक अधिसूचना जारी कर संसद के उप नियम द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या भाग को या जनजाति दल के हिस्से को या समुदाय को शामिल किया या निकाला जा सकता है। परन्तु उक्त खंड के तहत जारी की गई अधिसूचना के तदुपरांत किसी परवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।



डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. दिनांक 25.05.2016 तथा 15.11.2016 को हुई मंत्रिमंडल के अपने बैठक में दिये गये अनुमोदन तथा मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर एक विधेयक जिसका नाम ''संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पास किया गया जिसमें असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा के विद्यमान अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन तथा शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है।

6. त्रिपुरा राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में 9वें स्थान पर 'डारलोंग' को एक उप जनजाति कुकी को शामिल करने का प्रस्ताव के लिए संसद के संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। 'डारलोंग' की एक उप जनजाति कुकी को शामिल करने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार के प्रस्ताव/सिफारिश को भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पेज 17–21/सी में शामिल किया गया। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1950 में संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक, 2019 के नाम से विधेयक पारित करने के लिए मंत्रिमंडल में अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

7. इस मामले में, यह उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 17.10.2014 को आयोग द्वारा अपनी 62वीं बैठक में इन मामलों पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा बैठक के सार को जनजातीय कार्य मंत्रालय में आयोग के पत्र NP/Service/Inclusion(Darlong)/ Tripura/2013/RU-II दिनांक 06.11.2018 के माध्यम से भेजा जा चुका है।

**(बैठक के दौरान मामले पर विस्तृत चर्चा हुई, आयोग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी तथा इसे तद्नुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय को सूचित करने का निर्णय लिया।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.-122.1** | **Draft note for Cabinet for revision of List of Scheduled Tribes (Sts) Notified under Article 342 of Constitution of India with respect to the State of Tripura.** |

**File No. Cabinet Note/02/MTA/2019/RU-II**

Ministry of Tribal Affairs has forwarded a copy of O.M. No.15025/02/2013-C&LM-1 dated October, 2018, received in the Commission July-August, 2019 and September, 2019 from Ministry of Tribal Affairs enclosing with a copy of letter no. SSJETA/WCD-08/2017/534/183 dated 10.09.2018 of Department Social Justice & Empowerment and Tribal Affairs, Government of Arunachal Pradesh on the above mentioned subject.

2 Ministry of Tribal Affairs has forwarded a copy of O.M. No.12016/15/2001-TA/C&LM-1(130) dated 31st October, 2019, received in the Commission enclosing with a copy of Draft Note for the Cabinet dated October, 2019 on the above mentioned subject.

3. In this context, it is stated that the Constitution of India enjoins on the State a special responsibility for the protection and development of Scheduled Tribes. Clause (25) of article 366 of the Constitution defines Scheduled Tribes as "ST means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal community as are deemed under article 342 to be ST for the purpose of this Constitution". According to the above mention provisions, the first specification of Scheduled Tribes in relation to a particular State or UT is by a notified Order of President, after consultation with the Stage Govt. or UT concerned. Any subsequent inclusion in or exclusion from and other modifications in list of ST can be made only through an amending Act of Parliament.

4. Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

5. The based on the approval given by the Cabinet in its meetings held on 25.5.2016 and 15.11.2016 to the proposals of the Ministry, a bill namely " The constitution SC/ST Order (Amendment) Bill,2016 containing proposals for inclusion and modifications in existing list of ST of Assam, Chhattisgarh, Tamil Nadu and Tripura.

6. The proposal is for introduction of a Bill in Parliament to amend the Constitution (ST) Order 1950 to give effect the inclusion of 'Darlong' as sub tribe of Kuki in entry 9 in the list of ST of the State of Tripura. The proposal/recommendation of State Government of Tripura for inclusion of 'Darlong' as sub tribe of 'Kuki' in the list of ST, concurrence of RGI and NCST at page 17-21/c. Approval of the Cabinet is solicited for introduction of Bill namely, the Constitution ST Orders (Amd.) Bill, 2019 further to amend the Constitution (ST) Order, 1950.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. In the instant case, it is mentioned that these matter has already been considered in the Commission's in its 62nd meeting held on 17.10.2014, and the extract of the proceedings of meeting was sent to the Ministry of Tribal Affairs vide Commission's letter No. NP/Service/Inclusion (Darlong)/Tripura/2013/RU-II dated 06.11.2018.

**(The matter was discussed in detail during the meeting, the Commission has approved the proposal and decided to inform the Ministry of Tribal Affairs accordingly.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.2 | अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में भारत के संविधान में अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में संशोधन के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट |

**फाइल सं0 Policy/05/2018/MTA(AP)/RU-II**

उपरोक्त वर्णित विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं0 12026/24/2012-C&LM-1 दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 की प्रति अग्रेषित किया है जो आयोग में ड्राफ्ट कैबिनेट नोट की प्रति के साथ दिनांक अक्टूबर, 2019 को प्राप्त हुआ।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि भारत का संविधान इस राज्य को जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष जिम्मेदारी का आदेश देता है। संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड(25) में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा इस प्रकार की दी गई है कि "अनुसूचित जनजाति अर्थात् ऐसी जनजातियां या जनजातीय समूह या भागों या दाय जिसके तहत ऐसी जनजातियां या जनजातीय समूह को संविधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति समझा जायेगा।" उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति का प्रथम विनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश के अधिसूचना द्वारा होता है। इसके उपरांत अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ भी शामिल करने या निकालने के लिए तथा अन्य संशोधनों के लिए केवल संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।

3. अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ भी शामिल करने या निकालने के लिए खंड (1) के तहत एक अधिसूचना जारी कर संसद के उप नियम द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या भाग को या जनजाति दल के हिस्से को या समुदाय को शामिल किया या निकाला जा सकता है। परन्तु उक्त खंड के तहत जारी की गई अधिसूचना के तदुपरांत किसी परवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य संशोधन करने तथा निर्धारित प्रारूप में शामिल करने या बाहर निकालने के दावे को तथा अन्य संशोधनों के लिए सरकार ने दिनांक 15.06.1999 तथा तत्पश्चात् 25.06.2002 को संशोधन किया।

5. इससे पूर्व 31.12.2018 को मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल के समक्ष एक नोट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 02.01.2019 को हुई अपने बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। 2019 के संसद सत्र के दौरान 13.02.2019 को राज्य सभा में "संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019 के नाम से पास किया गया। तथापि, विधेयक लोक सभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि 13.02.2019 को संसद सत्र समाप्त हो चुका था। इसलिए 16वीं लोक सभा का समापन हो गया तथा 17वीं लोक सभा में नई सरकार का गठन हुआ तथा विधेयक का समय समाप्त हो चुका था। अतः संसद में विधेयक को पारित कराने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसी समय झारखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक और प्रस्ताव भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के तरफ से सहमति दी गई जिसको पहले से शामिल करने के लिए दिए हुए प्रस्ताव के साथ समय समाप्त हो चुके विधेयक के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. अरूणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए एक टिप्पणी का प्रस्ताव है जो इस प्रकार हैः

1. क्रम सं0 1 में 'अबोर' (Abor) को हटाया जाए क्योंकि क्रम सं0 16 में 'आदि' (Adi) एक ही है।
2. क्रम सं0 6 में 'खम्पटी' (Khampti) के बदले में 'खाम्टी' (Khamti) को प्रतिस्थापित किया जाए।
3. क्रम सं0 8 में 'मिसमी कामन' (Mishmi-Kaman) (मिजु मिसमी) (Miju Mishmi), इदु (Idu) (Mishmi) और तारौन (Taraon) (डिगरू मिसमी) (Digaru Mishmi) को क्रम सं0 8 में प्रतिस्थापित किया जाए।
4. क्रम सं0 9 में 'मोम्बा' (Momba) के बदले 'मोनपा' (Monpa), 'मेम्बा' (Memba), 'सारतंग' (Sartang), 'साजोलोंग' (Sajolong) (मिजी) (Miji) को प्रतिस्थापित किया जाए।
5. अरूणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम सं0 10 में 'किसी नागा जनजाति' के बदले में 'नोक्टे' (Nocte), 'तांगसा' (Tangsa), 'तुत्सा' (Tutsa), 'वांचो (Wancho) को प्रतिस्थापित किया जाए।
6. अरूणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम सं0 16 पर 'योबिन' (Yobin) को प्रतिस्थापित किया जाए।

7. इस मामले में, यह उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 05.09.2018 तथा 27.09.2019 को आयोग द्वारा अपनी 106वे, 107वें तथा 120वीं बैठक में इन मामलों पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा बैठक के सार को जनजातीय कार्य मंत्रालय में आयोग के पत्र Policy/05/ 2018/MTA(AP)/RU-II दिनांक 06. 11.2018 तथा दूसरे पत्रांक YT/1/2019/STGAR/DEINEX/ RU-II दिनांक 01.10.2019 के माध्यम से भेजा जा चुका है।

**(बैठक के दौरान मामले पर विस्तृत चर्चा हुई, आयोग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी तथा तद्नुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय को सूचित करने का निर्णय लिया गया।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.-122.2** | **Draft note for Cabinet for revision of List of Scheduled Tribes (Sts) Notified under Article 342 of Constitution of India with respect to the State of Arunachal Pradesh.** |

**File No. Policy/05/2018/MTA(AP)/RU-II**

Ministry of Tribal Affairs has forwarded a copy of O.M. No.12026/24/2012-C&LM-1 dated 31st October, 2019, received in the Commission enclosing with a copy of Draft Note for the Cabinet dated October, 2019 on the above mentioned subject.

2. In this context, it is stated that the Constitution of India enjoins on the State a special responsibility for the protection and development of Scheduled Tribes. Clause (25) of article 366 of the Constitution defines Scheduled Tribes as "ST means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal community as are deemed under article 342 to be ST for the purpose of this Constitution". According to the above mention provisions, the first specification of Scheduled Tribes in relation to a particular State or UT is by a notified Order of President, after consultation with the Stage Govt. or UT concerned. Any subsequent inclusion in or exclusion from and other modifications in list of ST can be made only through an amending Act of Parliament.

3. Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

4. The Government on 15.6.1999, and further amended on 25.6.2002, laid down modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modification in Order specifying ST/ST lists.

5. Earlier, on 31.12.2018 a Note for the Cabinet was submitted to Cabinet and the Cabinet in its meeting held on 02.01.2019 had approved the proposal. The Bill namely "The constitution SC/ST Order (Third Amendment) Bill, 2019 was passed in Rajya Sabha on 13.02.2019 during Parliament Session 2019. However the Bill could not be introduced in Lok abha as the Parliament was concluded on 13.02.2019. Since the 16th Lok Sabha has been dissolved and new Government has been formed in the 17th Lok Sabha and the Bill has been lapsed, So there is a requirement for approval of the Cabinet for introduction of the Bill in the Parliament. In the meantime one more proposals of the State Government of Jharkhand for inclusion in the list of ST of Jharkhand has been concurred by both RGI and NCST which also needs to be taken up along with proposals already included in the lapsed Bill.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. The proposal in this note is to amend the Constitution (ST) Order 1950 by amending the list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh, as under:-

1. Deletion of 'Abor' in Serial No.1, as it is the same as 'Adi' in Serial No.16.
2. Replace 'Tai Khamti' instead of 'Khampti' at Serial No.6.
3. Inclusion of 'Mishmi-Kaman' (Miju Mishmi), Idu (Mishmi) and Taraon (Digaru Mishmi) in Serial No.8.
4. Inclusion of Monpa, Memba, Sartang, Sajolang (Miji) in Serial No.9 in lieu of 'Momba'.
5. Inclusion of 'Nocte', 'Tangsa', 'Tutsa', 'Wancho' in lieu of 'Any Naga Tribes' in Serial No.10 in list of ST of Arunachal Pradesh.
6. Inclusion of 'Yobin' at serial No.16 in list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh.

6. In the instant case, it is mentioned that these matters has already been considered in the Commission's in its 106th , 107th and 120th meeting dated 05.09.2018 and 27.9.2019 and the extract of the proceedings meeting (s) were sent to the Ministry of Tribal Affairs vide Commission's letter No. Policy/05/2018/MTA(AP)/RU-II dated 06.11.2018 and another letter No.YT/1/2019/STGAR/DEINEX/RU-II dated 01.10.2019.

**(The matter was discussed in detail, The Commission has approved the proposal and decided to apprise the Ministry of Tribal Affairs accordingly.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.3 | संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के संशोधन का प्रस्ताव–ओडिशा राज्य के संबंध में |

**फाइल सं0 Policy/9/2019/MoTA(C&LM)/RU-III**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 28.01.2019 के पत्र सं0 12026/44/2013–सी एंड एलएम के द्वारा ओडिशा के अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम सं. 31 पर 'कंध' (Kandha) समुदाय के उप–समूह के रूप में 'कंध–कुंभार' (Kandha Kumbhar) समुदाय के रूप में समावेशन करने और क्रम सं0 53 पर उरांव (Oraon) के समानार्थी 'उराम/ओराम (Uram/Oraon), 'उरांव/धांगड़ा' (Oraon/Dhangra) तथा 'उरांव मुडी' (Oraon Mudi) के समावेशन करने के संबंध में ड्राफ्ट कैबिनेट नोट की एक प्रति भेजी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी टिप्पणी भेजने हेतु अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव समुदायों का समावेशन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में निम्न संशोधन करने के लिए हैं–

(i) क्रम सं0 31 पर 'कंध' (Kandha) अनुसूचित जनजाति के उप–समूह के रूप में 'कंध कुंभार' (Kandha Kumbhar)

(ii) ओडिशा के अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम सं0 53 पर सूचीबद्ध 'ओरांव' (Oraon) के समानार्थी 'उराम/ओराम' (Uram/Oram), उरांव/धांगड़ा' (Oraon/ Dhangara) तथा 'ओरांव मुडी' (Oraon Mudi)

ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम सं0 31 पर 'कंध' समुदाय के उप–समूह के रूप में 'कंध–कुंभार' समुदाय का समावेशन के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित नियमों के अनुसार भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मान लिया गया है।

ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम सं0 53 पर उरांव के समानार्थी 'उराम/ओराम, उरांव/धांगड़ा (Uram/Oram, Uraon/Dhangara) तथा ओरांव मुडी (Oraon Mudi) का समावेशन करने के प्रस्ताव को आयोग की 111वीं बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मान लिया गया परंतु भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने ओरांव के समानार्थी केवल उरांव (Oraon) के समावेशन के लिए अपनी सहमति दी है।

**(बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया गया, आयोग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.- 122.3** | **Proposal to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 - with respect to the State of Odisha.** |

**File no. - Policy/9/2019/MoTA(C&LM)/RU-III**

The Ministry of Tribal Affairs vide letter no. 12026/44/2013-C&LM dated 28/01/2019 has forwarded a copy of Draft Note for the Cabinet regarding inclusion of 'Kandha Kumbhar' community as a sub-set of 'Kandha' community at Sl. No. 31 and inclusion of 'Uram/Oram' , Uraon/Dhangara and 'Oraon Mudi' communities as synonyms of Oraon at Sl. No. 53 in the list of STs of Odisha. The MoTA has requested to NCST to send their comments.

The proposal is for amend the Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950 for inclusion of communities, namely

(i) 'Kandha Kumbhar' community as a subset of 'Kandha' Scheduled Tribe at serial number 31 and

(ii) 'Uram/Oram, Uraon/Dhangara and 'Oraon Mudi' communities as synonyms of 'Oraon' listed at serial number 53 in the list of Scheduled Tribes of Odisha.

The proposal of State Government for inclusion of 'Kandha Kumbhar' community as a sub-set of 'Kandha' community at Sl. No. 31 in the list of Scheduled Tribes of the State of Odisha has been concurred by RGI and NCST as per approved modalities.

The proposal for inclusion of 'Uram/Oram', 'Uraon/Dhangara' and 'Oraon Mudi' communities as synonyms of Oraon at Sl. No. 53 in the list of Scheduled Tribes of the State of Odisha has been concurred by NCST in 111th Meeting of the Commission but RGI has only concurred for inclusion of 'Uraon' as synonym of 'Oraon'.

**(The proposal of the Ministry of Tribal Affairs was considered in detail in the meeting, the Commission has approved the proposal.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.4 | छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची का संशोधन। |

फाइल सं0 **Policy/8/2019/MoTA(C&LM)/RU-III**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2019 के पत्र सं0 12026/91/2015–सी एण्ड एलएम(12251) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में संशोधन करने के संबंध में ड्राफ्ट कैबिनेट नोट की एक प्रति भेजी है।

यह प्रस्ताव निम्नलिखित समावेशनों को प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश करने के लिए है :–

(i) क्रम सं0 5 पर भारिया भूमिया (Bharia Bhumia) के समानार्थी भूईंया (Bhuinya), भूईयाँ (Bhuiyan), भूयां (Bhuyan)

(ii) क्रम सं0 14 पर धनवार (Dhanwar) के समानार्थी धनुहार/धनुवार (Dhanuhar/Dhanuwar)

(iii) क्रम सं0 32 पर नगेसिया (Nagesia), नागासिया (Nagasia) के समानार्थी किसान (Kisan)

(iv) क्रम सं0 41 पर सावर (Sawar), सवरा (Sawara) के समानार्थी सौंरा (Saunra), संवरा (Saonra)

(v) धांगड़ के साथ प्रतिस्थापित करते हुए क्रम सं0 33 पर अधिसूचित हिंदी रूपांतरण में सुधार

(vi) क्रम सं0 43 पर बिंझिया (Binjhia)

(vii) क्रम सं0 27 पर कोडाकू के अन्य देवनागरी रूपांतरण के रूप में कोडाकू के साथ–साथ कोड़ाकू

(viii) क्रम सं0 23 पर कोंध (Kondh) के साथ–साथ कोंद (Kond)

(ix) क्रम सं0 5 पर भारिया नाम के अंग्रेजी रूपांतरण में बिना परिवर्तन किए हुए भरिया के पक्ष में भारिया का सुधार

(x) क्रम सं0 5 पर पंडो, पण्डो/पन्डो

(xi) क्रम सं0 16 पर गोंड़ तथा गोंड

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(xii) अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम सं0 15 पर अंग्रेजी रूपांतरण में बिना परिवर्तन किए हुए गदबा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने समय–समय पर जारी किए गए पत्रों के द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का पहले ही समर्थन किया था। उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए विधायी विभाग के साथ परामर्श करते हुए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुबंध–V) के नाम से एक विधेयक तैयार किया गया है।

**(प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, आयोग ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट में उल्लेखित प्रस्ताव का समर्थन किया)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| Agenda item No.- 122.4 | Revision of List of Scheduled Tribe (STs) notified under Article 342 of Constitution of India with respect to the State of Chhattisgarh. |
|---|---|

**File no. - Policy/8/2019/MoTA(C&LM)/RU-III**

The Ministry of Tribal Affairs vide letter no. 12026/91/2015-C&LM(12251) dated 31/10/2019 has forwarded the copy of Draft Note for the Cabinet regarding revision of list of Scheduled Tribe (STs) notified under Article 342 of Constitution of India with respect to the State of Chhattisgarh.

The proposal is for introduction of a Bill in Parliament to amend the Constitution (Scheduled Tribe) Order 1950 with respect to the State of Chhattisgarh to give effect the following inclusions:

(i) Bhuinya (भूईंया), Bhuiyan (भूईयाँ), Bhuyan(भूयां) as synonyms of Bharia Bhumia (भारिया भूमिया) at entry No.5

(ii) Dhanuhar/Dhanuwar(धनुहार/धनुवार) as synonyms of Dhanwar(धनवार) at entry No.14

(iii) Kisan (किसान) as synonym of Nagesia(नगेसिया), Nagasia(नागासिया) at entry No. 32

(iv) Saunra (सौंरा), Saonra(संवरा) as synonyms of Sawar(सावर), Sawara(सवरा) at entry No.41

(v) Rectification of " in Hindi version notified at entry No.33 by substitution with 'धांगड़'

(vi) 'Binjhia(बिंझिया)' at entry No.43

(vii) कोड़ाकू along with कोडाकू as a variant Devanagari version of Kodaku at entry No. 27

(viii) कोंद (Kond) along with Kondh (कोंध) at entry No.23

(ix) Correction of भारिया as भरिया without changing its English version name Bharia at entry No.5

(x) पंडो ,पण्डो/पन्डो at entry No.5

(xi) गोंड़ and गोंड at entry No. 16

(xii) गदबा at entry No. 15 in ST list without change in English text

NCST had already supported the above proposals vide letters issued on number of occasions.

To give effect to the proposals contained above, a Bill namely, "The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2019 (Annexure-V) has been prepared in consultation with the Legislative Department.

**(After detailed discussion, the Commission supports the proposal mentioned in the draft Cabinet Note.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**
**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.5 | मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के संबंध में। |

**फाइल सं0 Policy/6/2019/MHA(J&PP Section)/RU-III**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 25.10.2019 के पत्र सं0 20025/44/2019– एनसीएसटी के द्वारा उपरोक्त विषय पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 14/06/2019– Judl&PP दिनांक अक्टूबर, 2019 प्रेषित किया है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस मामले पर जानकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) अध्यादेश में संशोधन के मुख्य अंश निम्नलिखित हैः–

(1) धारा 4 में, उप धारा (1) में, खंड (ख) में ''पच्चीस'' शब्द की जगह ''पांच हजार'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) धारा 7 में उप धारा (1) के लिए (1) में निम्नलिखित उप–खंड प्रतिस्थापित होगा, जिनके नाम हैः–

(i) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ऋण दर पर, किसी भी ऋणदाता को कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(ii) उप धारा (2) को हटाया जाएगा।

(iii) उप धारा (3) में, उप धारा (2) के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रभार से अधिक की जगह ''अन्य प्रभार'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) खंड 24 में–(i) ''छः महीना'' की जगह ''दो वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा (ii) ''एक हजार'' की जगह ''एक लाख'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) धारा 24 के बाद, निम्नलिखित खंडों को अंतर्स्थापित किया जाएगाः– 24क– इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी ऋणदाता द्वारा किसी की ऋण के लिए या उस पर लगाया गया ब्याज निष्फल और अपरिवर्तनीय होगा तथा इस तरह के ऋण और ब्याज के लिए कानून के किसी भी अदालत में कोई कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

(5) धारा 25 में, उप धारा (i) में ''एक हजार पांच सौ'' शब्द के लिए ''पच्चीस हजार'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

यह अध्यादेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में होगा और राज्य में ऋणदाताओं से उनकी रक्षा करना इस अध्यादेश का लक्ष्य होगा।

**(प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, आयोग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी क्योंकि यह मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों के हित में है।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/Dr. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.- 122.5** | **The Madhya Pradesh Anusuchit Janjati Sahukar Viniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019-reg .** |

**File no. - Policy/6/2019/MHA (J&PP Section)/RU-III**

The Ministry of Tribal Affairs vide letter no. 20025/44/2019-NCST dated 25/10/2019 has forwarded Ministry of Home Affairs OM No 14/06//2019-Judl &PP dated October, 2019 on the above mentioned subject and requested to NCST provide inputs on this matter.

Following are the highlights of amendments in Madhya Pradesh Anusuchit Janjati Sahukar Viniyam (Sanshodhan) Adhyadesh :-

(1) In section 4, in sub section (1), in clause (b) for the words "twenty -five" the words "five thousand" shall be substituted.

(2) In section 7, (1) for sub section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-

(i) No money lender shall charge, on any loan advanced, interest at a rate higher than that notified by the State Government from time to time.

(ii) sub- section (2) shall be omitted.

(iii) in sub-section (3), for the words "charge in excess of that prescribed under sub-section (2), the words "other charges" shall be substituted.

(3) In section 24,- (i) for the words "six months", the words "two years" shall be substituted, and (ii) for the words "one thousand", the words " one lakh" shall be substituted.

(4) After section 24, the following section shall be inserted, namely:-

24A - Any loan advanced or interest charged thereon by a money lender without obtaining a license under Section 3 of these Regulations shall be infructuous and irrecoverable and no legal proceedings shall be admissible in respect of such loan and interest in any court of law."

(5) In section 25, in sub-section (i) for the words " one thousand five hundred", the words " twenty five thousand" shall be substituted.

The ordinance seems to be in favour of Scheduled Tribes of the State and aims to protect them from money lenders in the State.

**(After detailed discussion, the Commission approved the proposal since it is for the benefit of Scheduled Tribes of the State of Madhya Pradesh)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**
**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| कार्यसूची मद सं0 122.6 | छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची में ''Bhuyya, bhiyan'' समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव के संबंध में। |

**FILE NO- INCLUSION/2017/MTA/RU-III**

जनजातीय कार्य मंत्रालय से दिनांक 01.11.2019 को पत्र सं0 -12026/11/2010C&LM-I प्राप्त हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में क्रम सं0 5 पर सूचीबद्ध ' Bharia Bhumia' के समानार्थी के रूप में ''Bhuyya, Bhiyan'' समुदायों को शामिल करने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियाँ मांगी है।

2013 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति सूची में भारिया भूमिया के समानार्थी के रूप में पांच समुदायों )i) Bhuinya) ii) Bhuiyan )iii) Bhuyan ) iv)Bhuyya )v) Bhiyan को शामिल करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी। राज्य सरकार के सहायक साक्ष्य के साथ–साथ उपलब्ध प्रकाशित सूचना के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति सूची में Bhuinya, Bhuiyan और Bhuyan को Bharia Bhumia के समानार्थी के रूप में पहले तीन समुदायों को शामिल करने का समर्थन किया है। चूंकि उस समय आसानी से कोई सहायक सूचना उपलब्ध नहीं हुई थी। शेष दो प्रस्तावित समुदाय भुय्या और भियान ने छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति सूची में उनके शामिल होने को समर्थन नहीं किया। अब राज्य सरकार ने भूय्या और भियान को शामिल करने के समर्थन में और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

भारत के महापंजीयक का कार्यालय, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में भूय्या और भियान को Bharia, Bhumia के समानार्थी के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

**(विस्तार से चर्चा करने के बाद, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची में भारिया (Bharia), भूमिया (Bhumia) के पर्याय के रूप में भुरया तथा भियान (Bhuyya, Bhiyan) समुदाय को शामिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव का, आयोग समर्थन करता है।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.- 122.6** | **Proposal for inclusion of "Bhuyya, Bhiyan" community in the Scheduled Tribes list of Chhattisgarh-reg.** |

**FILE NO- INCLUSION/2017/MTA/RU-III**

The ministry of Tribal affairs vide letter no. 12026/11/2010-C&LM-I dated 01/11/2019 has received. MoTA seeking comments of NCST on inclusion of "Bhuyya, Bhiyan" communities as synonyms of 'Bharia Bhumia' listed at Sl.No. 5 in the Scheduled Tribes list of Chhattisgarh.

In 2013 the proposal for inclusion of five communities viz. (i) Bhuinya (ii) Bhuiyan (iii) Bhuyan (iv) Bhuyya (v) Bhiyan as synonyms of Bharia Bhumia in the Scheduled Tribes list of the Chhattisgarh was examined by the MoTA. Based on the available published information as well supporting evidences of the State Government. MoTA supported the inclusion of first three communities namely Bhuinya, Bhuiyan and Bhuyan as synonyms of Bharia Bhumia in the STs list of Chhattisgarh. As there was no supporting informaion readily available at that time. The remaining two proposed communities i.e Bhuyya and Bhiyan not supported their inclusion in the STs list of Chhattisgarh. Now the State Government has furnished further evidences in support for inclusion of Bhuyya and Bhiyan.

The ORGI supports the proposal for inclusion of Bhuyya and Bhiyan as synonyms of Bharia, Bhumia in the list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh.

**(After detailed discussion, the Commission supports the proposal of the Ministry of Tribal Affairs for inclusion of Bhuyya and Bhiyan community as synonyms of Bharia, Bhumia in the list of STs of Chhattisgarh.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.7 | ओडिशा के अनुसूचित जनजातियों की सूची में " KULI" समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव के संबंध में। |

**FILE NO- INCLUSION/2017/MTA/RU-III**

जनजातीय कार्य मंत्रालय से दिनांक 05.11.2019 के पत्र सं0 -12026/29/2012C&LM-I प्राप्त हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनजातियों की सूची में" KULI "समुदाय को शामिल करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रति, भारत के महापंजीयक व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु भेज दी है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सीए सं0 7362/2019 में पारित हुआ कि 'ओडिशा राज्य में 'KULIS' नाम से कोई समुदाय नहीं है। एकमात्र " KULI " समुदाय है। यदि हम " KULI " में " KULIS " को शामिल नहीं करते हैं, तो अंतिम परिणाम यह होगा कि हम अनुसूचित जनजाति की सूची से एक जनजाति को हटा देंगे। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने भी 'सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन किया और बताया कि उनके विचार से अंग्रेजी संस्करण के "KULIS "शब्द को" KULI "समुदाय के सदस्य में शामिल किया जाए।

ओडिशा की राज्य सरकार ने ओडिशा की अनुसूचित जनजाति की सूची में "KULI "को शामिल करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है क्योंकि समुदाय "KULIS" को पहले ही अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम सं0 42 में शामिल किया जा चुका है।

**(प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरांत आयोग ने सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया जो उड़ीसा सरकार से प्राप्त औचित्य के अधीन एवं भारत के पंजीयक द्वारा समर्थन प्राप्त हो।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.- 122.7** | **Proposal for inclusion of "Kuli" community in the Scheduled Tribes list of Odisha-reg.** |

**FILE NO- INCLUSION/2017/MTA/RU-III**

The ministry of Tribal affairs vide letter no.12026/29/2012-C&LM dated 05/11/2019 has received. The Supreme Court has given directions in respect of inclusion of community "KULI" in list of tribes. The MoTA has been forwarded the copy of judgment of the Supreme Court to RGI and NCST to obtaining their comments.

Judgment of Hon'ble Supreme Court of India passed in CA No. 7362/2013 that 'there is no community by the name "KULIS" in the State of Odisha. The only Community is "KULI". If we don't include "KULI" in "KULIS", the net result would be that we would be deleting a tribe from the list of Scheduled Tribes. Further, Hon'ble Court also observed that "Taking all the above facts into consideration, in the peculiar facts and circumstances of the case, we are of the view that the term "KULIs" in the English version will be include members of the "KULI" community.

State Government of Odisha has requested to take appropriate steps to include "KULI" in the ST list of Odisha as the community "KULIS" has already been included at SI. No. 42 of ST list of Odisha.

**(The matter was discussed in detail, the Commission has supported the proposal in principal, subject to justification received from the Government of Odisha and supported by the Registrar General of India.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 122.8 | **झारखंड राज्य के संबंध में भारत के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में संशोधन का प्रस्ताव।** |

**File no. - Policy/7/2019/MoTA(C&LM)/RU-III**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2019 के पत्र सं0 – 12026/05/2015C&LM द्वारा झारखंड राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में संशोधन करने के संबंध में ड्राफ्ट कैबिनेट नोट की एक प्रति भेजी है।

यह प्रस्ताव निम्नलिखित समावेशनों को प्रभावी करने के लिए झारखंड राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश करने के लिए है:–

(1) अनुसूचित जाति की सूची में क्रम सं0 3 पर सूचीबद्ध भोगता समुदाय को हटाया जाए और

(2) अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित समुदायों को शामिल करने के लिए:–

(i) नई प्रविष्टि के रूप में पुरान )puran); तथा

(ii) क्रम सं0 16 पर सूचीबद्ध Kharwar (खरवार) के समानार्थी के रूप में Bhogta (भोगता), Deshwari (देशवारी), Ganjhu (गंझू), Dautalbandi (Dwalbandi) (दौलतबंदी) (द्वालबंदी), Patbandi (पटबन्दी) Raut (राउत), Maajhia (माझिया) Khairi (खैरी) (Kheri) (खेरी)

(iii) क्रम सं0 24 में 'Munda' (मुंडा) के समानार्थी के रूप में Tamaria/Tamadia (तमरिया/तमड़िया)।

झारखंड राज्य सरकार का प्रस्ताव/सिफारिश, झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में उपरोक्त समुदायों को शामिल करने के लिए भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति ड्राफ्ट नोट के साथ संलग्न की गई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने समय–समय पर जारी किए गए पत्रों के द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का पहले ही समर्थन किया था। उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए विधायी विभाग के साथ परामर्श करते हुए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुबंध–V) के नाम से एक विधेयक तैयार किया गया है।

**(विस्तार से चर्चा करने के बाद, आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन करता है।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda item No.- 122.8** | **Revision of List of Scheduled Tribe (STs) notified under Article 342 of Constitution of India with respect to the State of Jharkhand.** |

**File no. - Policy/7/2019/MoTA(C&LM)/RU-III**

The Ministry of Tribal Affairs vide letter no. 12026/05/2015-C&LM dated 31/10/2019 has forwarded the copy of Draft Note for the Cabinet regarding revision of list of Scheduled Tribe (STs) notified under Article 342 of Constitution of India with respect to the State of Jharkhand.

The proposal is for introduction of a Bill in Parliament to amend the Constitution (Scheduled Cast) order 1950+ and the Constitution (Scheduled Tribe) Order 1950 with respect to the State of Jharkhand to give effect the following:

(1) to omit Bhogta community listed at serial No. 3 in the list of Scheduled Castes and

(2) to include the following communities in the list of Scheduled Tribes:-

(i) Puran (पुरान) as new entry; and

(ii) Bhogta (भोगता), Deshwari (देशवारी), Ganjhu(गंझू), Dautalbandi (Dwalbandi)[दौलतबंदी)द्वालबंदी(], Patbandi(पटबन्दी), Raut(राउत), Maajhia(माझिया), Khairi(Kheri)[खैरी)खेरी(] as synonyms of Kharwar (खरवार) entry at S.N. 16

(iii) Tamaria/Tamadia (तमरिया/तमड़िया) as synonym of 'Munda'(मुंडा) at S.No.24

The proposal/recommendation of State Govt. of Jharkhand, concurrence of RGI and NCST for inclusion of above mentioned community in list of Scheduled Tribe list of Jharkhand has been enclosed with the draft note.

To give effect to the proposals contained above, a Bill namely, "The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2019 has been prepared in consultation with the Legislative Department.

**(After detailed discussion, the Commission supports the proposal of the Ministry.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सं0 9 | अनुसूचित जनजाति के लिए आंध्र प्रदेश राज्य आयोग के संविधान के संबंध में 2003 के अधिनियम 9 में संशोधन–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः दो पृथक संविधान। |

**फाइल सं0 (Policy/AP/2019/RU-IV)**

आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए अधिनियम सं0 9/2003 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य आयोग का सृजन किया है। अधिनियम सं0 9/2003 में संविधान के तहत या किसी कानून के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित मामले की पूछताछ, जांच–पड़ताल तथा निगरानी से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की ओर से सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत संरक्षण के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए कार्यरत विभिन्न संरक्षणों तथा नागरिक अधिकारों के लिए कार्यों का मूल्यांकन का भी कार्य करता है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 59.18 लाख है जो कि कुल आबादी का 6.99 प्रतिशत है। इसलिए अनुसूचित जनजातियों के हित में तथा अधिकारों के संरक्षण में कार्य कर रहे विभिन्न रक्षोपायों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों तथा अधिकारों की समीक्षा के तहत कार्यान्वयन की नीति की समीक्षा के तहत कार्यान्वयन की नीति की समीक्षा तथा कार्यान्वयन के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सिफारिशें तैयार करने और नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा के प्रवर्तन तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1955 तथा आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण नियमावली 1959 तथा अन्य कानूनों एवं नियमावलियों जैसे कि ROFR को जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया, को आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य आयोग में उचित संशोधन करके एक विशेष राज्य आयोग का कानून बनाना चाहती है जिसका गठन 2003 के अधिनियम 9 के तहत किया गया था।

अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राज्य आयोग के गठन से संबंधित मामले को दिनांक 12/12/2019 को आयोजित हुई आंध्र प्रदेश जनजाति परामर्श परिषद् की बैठक के समक्ष रखा गया था तथा परिषद् ने अपने संकल्प संख्या 3 में निम्नलिखित सदस्यों के माध्यम से पृथक आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सृजन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया हैः–

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. इन तीन सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिला होंगी।

आंध्र प्रदेश सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सहयोग करने का अनुरोध करती है तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार कर सूचित करे जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 9 के तहत आवश्यक बनाया गया है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जैसा कि संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा तथा संरक्षण का प्रबंध किया गया है राज्य सरकार के प्रस्ताव में अनुसरण किया गया है। इसलिए आयोग प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने पर विचार कर सकता है।

**(आंध्रप्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया तथा आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति दी। तद्नुसार आयोग के निर्णय को राज्य सरकार को संसूचित किया जाए।)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| AGENDA ITEM No. 9 | AMENDMENT TO ACT 9 OF 2003 REGARDING THE CONSTITUTION OF ANDHRA PRADESH STATE COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES - CONSTITUTION OF TWO SEPARATE COMMISSIONS FOR SCS & STS RESPECTIVELY |
|---|---|

(Policy/AP/2019/RU-IV)

The Government of Andhra Pradesh has created A.P. State Commission for SCs and STs by Act No. 9/2003. The Act No. 9/2003 has provided for the Commission for SCs and STs to perform functions related to enquiry, investigating and monitoring of matters relating to the safeguard provided for the SCs and STs under Constitution or under any Law and also evaluate the working of various safeguards and civil rights accruing to SCs and /STs under protection of Civil Rights Act, 1955 and protecting to Atrocity Act, 1989. The Scheduled Tribe population in Andhra Pradesh is 59.18 Lakhs as per 2011 Census constituting 6.99% to the total population of the State. Therefore for effective evaluation of working of various safeguards and to protect rights and interests of Scheduled Tribes and to undertake a review of rights and interests of Scheduled Tribes and to undertake a review of implementation of the policies and to make recommendations with a view to ensue effective implementation and enforcement of alt safeguards under Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer Regulation 1959 as amended from time to time and other laws and the rules like ROFR, the Government of Andhra Pradesh proposes to enact an exclusive State Commission for Scheduled Tribes by suitably amending the existing A.P. State Commission for SC & ST which was constituted under Act 9 of 2003.

The issue pertaining to constituting a separate State Commission for STs was placed before the A.P. Tribes Advisory Council in the meeting held on 12.12.2019 and the Council unanimously resolved for creation of separate A.P. ST Commission through their resolution No. 3 with members as follows.

1. Chairman,
2. Vice Chairman
3. Three members of these at least one shall be a woman member.

The Government of Andhra Pradesh requested the NCST to Concur the proposal and convey the views on the above proposal as required under clause 9 of the Article 338-A of the Constitution of India.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

As the proposal of the State Government is in line with the safeguards and protection provided to the Scheduled Tribes under the Constitution.Therefore, the Commission may consider to concur the proposal.

**(The Commission considered the proposal of the State Government of Andhra Pradesh and agreed with the proposal. Accordingly, the decision of the Commission may be conveyed to the State Government.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| Agenda Item: 10 | Strengthening of Units at NCST Headquarter and Regional Offices by providing minimal manpower for effective function as per the mandate of NCST. |
|---|---|

Since its creation vide Constitution (89th Amendment) Act, 2003, National Commission for Scheduled Tribes is facing shortage of officers and staff and due to retirement of the officers and officials over the years, the situation has further worsened. NCST is finding it difficult to function effectively as per the mandate given in the Constitution of India. At present, out of sanctioned strength of 124, only 50 regular officers and officials are working in NCST headquarter and its six Regional offices. A large number of posts are vacant due to the reason that the cadre controlling authority of these posts were Department of Social Justice and Empowerment and National Commission for Scheduled Castes and these powers have been transferred to NCST a few months ago. The Recruitment Rules of most of the posts are being framed for filling them on regular basis which may take some time. Till then the work of the Commission should not suffer and necessary arrangement have to be made.

It has been seen that the Units in the Commission headquarter are manned with one AD/RO with multiple responsibilities and they are assisted by 01 Consultant/Sr. Investigator and 01 Data Entry Operator. This is highly inadequate to tackle the heavy work load of grievances and sittings in the Units and it is felt that examination of the replies received from the respondents needs to be improved by engaging specialist Consultants having knowledge on the subject particularly land matters, atrocities, constitutional provisions for Scheduled Tribes, reservation in posts and services, displacement and resettlement of tribals etc. Similarly, almost all the Regional Offices are presently headed by AD/RO level officers without any Sr. Investigator, Investigator or Consultant. In some Regional offices like Raipur and Shillong, there is nobody to even type the letters to initiate action on the grievances.

In view of the above, it is proposed to provide at least 01 or 02 Specialist Consultants in the Units of Commission headquarter (depending on work load) and its six Regional Offices. It is also proposed to provide 01 or 02 DEOs and Attendants (by way of out sourcing) to all the Units of Headquarter and the Regional Offices after assessment of work load.

**(After detailed discussion, the Commission strongly supported the proposal and observed that to improve the grievance redressal mechanisim and performance, it is necessary that all the units of headquarter and Regional Offices may be provided essential man power after following the due procedure and taking necessary approvals.)**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**National Commission for Scheduled Tribes**

**Minutes of the 122th Meeting held on 11-12-2019**

| | |
|---|---|
| **Agenda Item: 11** | **Regularisation of four MTS in NCST as per the Order of Hon'ble High Court of Delhi–reg.** |

**FILE NO- 9/2/NCST/2017-Estt**

The matter of regularization of services of four MTS employed in NCST headquarter and regional office, Ranchi in compliance of Hon'ble High Court, Delhi was discussed as an agenda item in the meeting. It was informed that In WP (C) NO.7937/2017& CM APPLN. 32765/2017 Judgement pronounced on 08th Jan, 2019 by Hon'ble Mr. Justice Suresh Kumar Kait in para 7 on page -6 as under:

"7. Learned counsel submits that the petitioners have completed more than 11 years of service. Therefore, they are entitled for regularisation as per para 444 & 53 of the judgement of Hon'ble Supreme Court in State of Karnataka and Ors. vs. Uma Devi and Ors.2006 SCC (L&S) 753".

Further, LPA220/2019 & CAV. 329/2019 & CM APPL.14676-78/2019 NCST (Appellants) Versus Jitendra Kumar & ORS (Respondents) in the Hon'ble High Court in Delhi. Hon'ble The Chief Justice and Hon'ble Mr. Anup Jairam Bhambhani passed Order on 01.04.2019 as under:

"The appeal is disposed of with a direction to the appellants to reinstate the respondents, continue them as MTS, allow them to work on ad-hoc basis till their cases for regularisation are considered in accordance to the law laid down in the case of State of Karnataka and Ors. vs. Uma Devi and Ors.2006 SCC (L&S)753".

NCST as per the direction of Hon'ble High Court, Hon'ble Mr. Justice Najmi Waziri (Order dated 01.04.2019) reinstated the petitioners as MTS on an ad-hoc basis vide order No. 9/2/NCST/2017-Estt. dated 08.04.2019 which includes Shri Jitendra Kumar (UR), Shri Pankaj (UR), Shri Sushil Kumar (SC) and Shri Pannu Singh Munda (ST).

On 14.11.2019 CONT.CAS ( C ) 213/2019 was heard in the Hon'ble High Court of Delhi and in this case Hon'ble Mr. Justice A K Chawala passed the Order dated 14.11.2019 as under:

"Copy of the order dated 31.08.2017 that was set aside vide judgement dated 08.01.2019 does not surface on record. Let a copy therefore be filed by the petitioners by way of an affidavit within two weeks. **List on 23.03.2020".**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Keeping in view the position explained above and MoTA's observations communicated to NCST vide letter No.120/02/2017-NCST dated 07.11.2019 MoTA was requested to inform the NCST whether a reply will be prepared by MoTA and to be submitted on behalf of the Secretary, MoTA or a reply will be submitted by the NCST in implementation of the Order dated 30.05.2019 of Hon'ble High Court of Delhi for regularisation as per the law laid down in the case of "State of Karnataka and Ors.vs. Uma Devi and Ors., 2006SCC (L&S)753".

Legal Consultant in NCST examined the case and has given his views which are as follows – Now the NCST is all set to comply the order dated 08.01.2019 in terms of their regularisation with all consequential benefits like seniority, pay and allowances from the date of their regularisation, in accordance with the law laid down in of State of Karnataka and Ors.vs. Uma Devi and Ors., 2006SCC (L&S)753.

**Accordingly the matter was placed before NCST as an agenda in the 122nd meeting of the Commission. The Commission after detailed deliberations, decided that NCST should go ahead with regularization of services of above four MTS after following the due procedure and necessary consultation with MoTA, being the administrative Ministry and other Ministries/Departments, if required.**

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi